भोपाल | रविवार | 9 अगस्त 2026 | वर्ष 70 | अंक 197 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 रांची में वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा

4 जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता

9 डेविस कप : सियोल में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा भारत

11 महाकाल से महाशक्ति तक की यात्रा अधूरी क्यों ?

जनता को न्याय का अधिकार

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में कहा

1 समानता और न्याय की पहुंच हर नागरिक तक हो

2 संवाद, गरिमा और संवदेनशीलता हमारी न्याय प्रणाली की आत्मा

नवभारत न्यूज

इंदौर, 8 अगस्त. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है. हर क्षेत्र और स्थान के अनुसार परेशानियों का प्रकार भी बदलता रहता है. जिस क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, हमें उसी क्षेत्र की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुसार संवाद करना चाहिए. जो न्याय की आस में आपके पास आया है, उसकी आधी परेशानी सिर्फ आपके व्यवहार से ही दूर हो जाती है. यदि आप उससे उसी की भाषा में सही तरह से संवाद करेंगे तो वह सहज होने लगेगा और आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ता जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत इंदौर में आयोजित 'इन्हेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस' विषय पर केंद्रित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप सभी को अधिकार दिलाने की बात करते हैं और कोई एक व्यक्ति भी उन अधिकारों को पाने में सफल नहीं होता तो आप फेल हो जाते हैं. इसलिए सभी को समान अधिकार मिलें यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो, इसी में समानता का भाव छिपा है. समानता सिर्फ शब्दों में नहीं वास्तविक अर्थों में भी आनी चाहिए, इसलिए जब खुद बड़ी भूमिका में आ जाएं, तो यह जरूर देखें कि हमारे बीच में से कोई पीछे तो नहीं रह गया? हमें प्रगति और अधिकार दिलाने की कोशिश में यह जरूर देखना होगा कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया? उन्होंने कहा कि समानता और न्याय की पहुंच हर नागरिक का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना भी हम सभी की ही जिम्मेदारी है. हमारी असली परीक्षा तो इस बात में है कि जो न्याय पाने के लिए हमारे पास नहीं आया है, हम उस तक कैसे पहुंचे?

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि न्याय पाना इस धरती में जन्मे हर व्यक्ति का प्राथमिक और मानवीय अधिकार है. एक जागरूक नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम समाज के हर उस पीड़ित व्यक्ति या समुदाय को न्याय के मंदिर तक न केवल पहुंचाएं, बल्कि उसे न्याय भी दिलवाएं, जो न्याय पाने का वास्तविक अधिकारी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी हो, जो सर्वव्यापी, सुलभ, सुगम, शीघ्र, सस्ती... ▶ शेष पेज 12 पर

न्याय की धरती पर यह आयोजन होना गर्व की बात : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की नगरी माता अहिल्याबाई होल्कर के न्याय के लिए जानी जाती है. उन्होंने न्याय के लिए अपने पुत्र और प्रजा में भी भेद नहीं किया. अपने पुत्र को भी दंड दिया और समाज को न्याय की सही परिभाषा दी. इसी तरह महाराज विक्रमादित्य ने भी अपनी धर्मपत्नी के भाई को मृत्युदंड दिया और समाज में न्याय स्थापित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता न्याय आधारित रही है. पंच परमेश्वर से लेकर राजा-महाराजा तक प्रजा को सही तरह से न्याय दिलाने में पूर्ण यकीन रखते थे. आज भारत में न्याय सभी की पहुंच में हो और सही समय पर मिले हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसके लिए सरकार और न्यायपालिका मिलकर काम कर रहे हैं.

कोई परेशानी लेकर आए तो ठीक तरह से संवाद करें

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब कोई न्याय के लिए आता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा है, आप उसे कितना सम्मान देते हैं, यह उसकी परेशानियों को आधा कम कर देता है. यदि आप उसकी परेशानी को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको उसका निदान करने में भी मुश्किल आएगी. इसलिए सही तरीके से संवाद करना सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा जिस तरह से डॉक्टर मरीज से बहुत शांत होकर, सकारात्मक तरीके से बात करते हैं और मरीज को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे. इसी तरह न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों और व्यवस्थाओं के लोगों को पीड़ित से इस तरह से संवाद करना चाहिए ताकि उसकी परेशानी कम हो.

भारत की ताकत युवा और डेटा

रील्स के नशे में फंसे युवा, रोजगार का संकट गहराया : राहुल

40 करोड़ युवा हैं देश में करीब और उनके पास बड़ी क्षमता है

01 हजार युवाओं में केवल 12 युवाओं को ही निजी क्षेत्र में नौकरी

प्रयागराज, 8 अगस्त. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवाओं के बीच बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश का युवा बड़ी क्षमता रखने के बावजूद मौजूदा व्यवस्था के 'चक्रव्यूह' में फंसा हुआ है. राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स को 21वीं सदी का 'नशा' बताते हुए कहा कि युवाओं को इसमें उलझाकर उनके भविष्य और रोजगार के सवाल से ध्यान भटकाया जा रहा है.

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में 'दर्द, डेटा और दौलत' को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी और डेटा है. उन्होंने दावा किया कि देश में करीब 40 करोड़ युवा हैं और उनके पास बड़ी क्षमता, कल्पनाशक्ति और प्रतिभा है. उनके मुताबिक, 21वीं सदी में किसी देश की प्रगति के लिए युवा शक्ति के साथ डेटा भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में डेटा बेहद अहम संपत्ति बन चुका है.

उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर कहा कि युवा इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता. राहुल गांधी ने दावा किया कि एक हजार युवाओं में केवल 12 युवाओं को ही निजी क्षेत्र में नौकरी मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि रोजगार का यह संकट युवाओं और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी युवाओं को आगाह किया. उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखना आज एक नए तरह का नशा बन गया है. उनके अनुसार, पढ़ाई और डिग्री हासिल करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर कई युवाओं को मजबूरी में डिलीवरी और कैब सेवाओं जैसी नौकरियों में लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है.

कार्यक्रम में एक युवक ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का खर्च उठाने के लिए उसे डिलीवरी का काम करना पड़ा. उसने सेना की परीक्षा भी दी, लेकिन एक अंक से असफल रहा. राहुल गांधी ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी परिस्थितियां मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में देश को आगे ले जाने की क्षमता है, लेकिन व्यवस्था को उनकी क्षमता को रोकने के बजाय उसे अवसर में बदलने की जरूरत है.

आतंक के खिलाफ सीआईके का एक्शन

कश्मीर के कई जिलों में छापे

श्रीनगर, 8 अगस्त. कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने शनिवार को कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया. अधिकारियों के मुताबिक बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपोरा समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई.

कार्रवाई ऑनलाइन आतंकवाद को बढ़ावा देने और युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती के लिए उकसाने से जुड़े मामले में की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सीआईके श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 03/2023 के तहत की जा रही है. मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 153-ए तथा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 लगाई गई हैं.

मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे. अगले साल प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हैं.

नियुक्तियों के लिए बनेगा राष्ट्रीय आयोग

लोकसभा में आएगा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक

नई दिल्ली, 8 अगस्त. न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र और एकरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पेश करने जा रही है.

प्रस्तावित कानून में विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्तियों, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तों और अन्य प्रावधानों को व्यवस्थित करने के साथ राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है. प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसमें एक अध्यक्ष समेत कुल पांच सदस्य होंगे. आयोग में दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य शामिल किए जाएंगे. अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पात्र होंगे. आयोग का उद्देश्य न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र और पेशेवर व्यवस्था तैयार करना है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक में न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता के साथ-साथ उनके चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है. इसके अलावा वेतन एवं भत्ते, इस्तीफा, पद से हटाने और सेवा की अन्य शर्तों से जुड़े प्रावधान भी प्रस्तावित कानून का हिस्सा होंगे. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पृष्ठभूमि में उठाया जा रहा है.

ग्राहकों के लिए मुफ्त रहेगा यूपीआई

छोटे कारोबारियों पर भी एमडीआर नहीं : पीसीआई

नई दिल्ली, 08 अगस्त. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा.

साथ ही, छोटे कारोबारियों को भी यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उद्योग संगठन ने कहा कि वर्ष 2016 में लॉन्च होने के बाद से ही यूपीआई उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहा है. पीसीआई ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों पर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाकर ही भारत बनेगा विश्वगुरु : मोहन भागवत

बुलढाणा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारत को सही मायनों में विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है. महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव में पारधी समुदाय के बच्चों के लिए बने एक आवासीय विद्यालय में तीन खेल मैदानों का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हर कोई चाहता है कि भारत विश्वगुरु बने.

पहला इको-एजुकेशनल हब राष्ट्र को समर्पित

नयी दिल्ली, 08 अगस्त. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को लखनऊ के बंथरा स्थित महर्षि पाराशर बायोरिसोर्स सेंटर में सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) द्वारा विकसित अपनी तरह के पहले इको-एजुकेशनल हब प्रकृति ज्ञान धाम को राष्ट्र को समर्पित किया.

डॉ. सिंह ने इस अवसर पर वैज्ञानिक संस्थानों से अपनी प्रौद्योगिकियों, सफल प्रयोगों और शोध के सामाजिक उपयोग को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को अपने अनुसंधान को आजीविका और समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना चाहिए. वैज्ञानिक उपलब्धियों की पहुंच केवल प्रयोगशालाओं और संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, उद्योगों और अन्य हितधारकों तक होनी चाहिए. उन्होंने इसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच समान एवं पूरक परियोजनाओं के एकीकरण की आवश्यकता बतायी. उन्होंने कहा कि एकीकृत वैज्ञानिक प्रयासों से उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग किया जा सकता है तथा अनुसंधान एवं नवाचार का सामाजिक प्रभाव अधिकतम किया जा सकता है.

आरबीआई और सहकारी बैंक मिलकर काम करें

- **शहरी सहकारी बैंकों को गृहमंत्री अमित शाह की नसीहत**
- **राज्य देश के 70 % शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं**

मुंबई, 8 अगस्त. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और शहरी सहकारी बैंकों के बीच आपसी विश्वास और बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को पुरानी धारणाओं से आगे बढ़कर मिलकर काम करना चाहिए.

मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में शाह ने कहा कि आरबीआई ने हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाया है और क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक संवाद जरूरी है.

शाह ने कहा कि सरकार और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र जब भी सकारात्मक तरीके से आरबीआई के पास पहुंचे, केंद्रीय बैंक ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए किए गए विभिन्न सुधारों का उल्लेख किया. इनमें शाखाओं के विस्तार के नियमों में ढील, घर-घर बैंकिंग सेवाओं की अनुमति, यूसीबी को डिमांड ड्राफ्ट और जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति तथा समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री ने हाल के नियामकीय सुधारों का भी स्वागत किया, जिनमें गोल्ड लोन की सीमा बढ़ाना और वन-टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था शामिल है. उन्होंने बताया कि शहरी सहकारी बैंकों में वर्तमान में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है. शाह ने कहा कि छोटे उधारकर्ता सहकारी बैंकों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित ऋण वर्ग साबित हो सकते हैं.

दीक्षांत समारोह | आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश- आपकी सोच और मेहनत तय करेगी भारत का भविष्य

जिंदगी की परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस

3000
छात्रों को ग्रेजुएट्स डिग्रियां

557
पीएचडी डिग्री भी बांटीं

नई दिल्ली, 8 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 35 साल देश के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं.

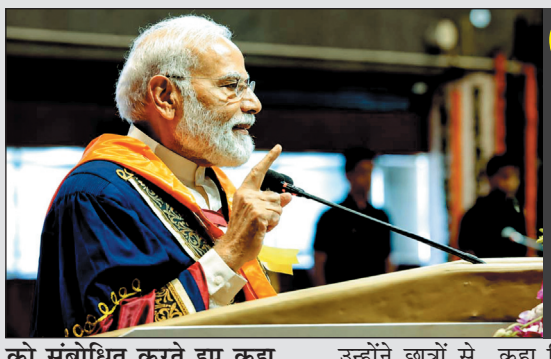

उन्होंने छात्रों से कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है, - हर पीढ़ी के लिए अपनी अलग चुनौतियां है.पीएम ने ये भी कहा कि सिर्फ समस्या पर चर्चा करने या सवाल उठाने के बजाय उसके व्यावहारिक समाधान पर ध्यान देना जरूरी है. पीएम ने 3,000 से अधिक ग्रेजुएट्स को डिग्रियां प्रदान कीं और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. साथ ही पीएम ने 557 पिएचडी डिग्री भी बाटें. उन्होंने कहा कि अगले 35 साल की मेहनत से विकसित भारत की नींव बनेगी.

इस दौरान पीएम मोदी मजाकिया अंदाज में बाबा बागेश्वर का जिक्र किया और कहा कि वह बाबा बागेश्वर तो नहीं हैं, लेकिन छात्रों के मन में भविष्य को लेकर कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि उनके सपने अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के विकास में उनकी भूमिका अहम होगी. उन्होंने युवाओं से कहा कि अगले 30-35 साल में उनके फैसलों का असर विकसित भारत के सफर पर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन एक लीडर बोर्ड नहीं है. आईआईटी कैंपस में आना सौभाग्य की बात है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार रखें. हर पीढ़ी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी इससे कोई मुखर नहीं सकता है. मोदी ने कैंपस जीवन और वास्तविक जीवन के अंतर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संस्थान में छात्रों को सिलेबस और परीक्षा की जानकारी होती है, लेकिन असली जिंदगी में कई चीजें 'आउट ऑफ सिलेबस' होती हैं. वहां व्यक्ति को खुद यह पहचानना पड़ता है कि वास्तविक समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे खोजा जाए. उन्होंने आईआईटी के पूर्व छात्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोगों ने ऐसी समस्याओं को पहचाना, जिन पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था. प्रधानमंत्री ने छात्रों को अपने सपनों पर काम करने और नई संभावनाओं की तलाश करने की सलाह दी. दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए और विद्यार्थियों को डिग्रियां दीं.